



HRA an USIUA The Gazette of India

असाधार**ए** EXTRAORDINA**R**Y

with II—was 3—sq-squs (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

d• 257]

नई बिल्ली, शतिबार, जून 6, 1992/ ज्येष्ठ 16, 1914

No. 257] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 6, 1992/JYAISTHA 16, 1914

इस भाग में भिम्न पृष्ट संस्था वी बाती है जिससे कि यह जलग संकालन के रूप में एका बा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विस्त मंत्रालय (ग्राधिक कार्य विभाग) (वेंकिंग प्रभाग)

मधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 1992

सा.का.नि. 585(ग).--केन्द्रीय सरकार, विशेष त्यायालय (प्रति-भूति संब्यवहार संबंधी अपराध विचारण) प्रध्यादेश, 1992 की धारा 14 द्वारा प्रयत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखिन नियम बनाती है, प्रयात्:---

- (1) संक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारम्भः (1) इन] नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार संबंधी श्रपराध विचारण) नियम, 1992 है।
 - (2) ये राजपल में प्रकाशन की तारीख को प्रवृक्त होंगे।
- 2. जानकारी के क्लोत :— विशेष न्यायालय (प्रतिभृति संव्यवहार संबंधी सपराध विकारण) सध्यादेश, 1992 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सध्यादेश कहा गया है) झारा 3 की उपधारा (1) के अधीन सियुक्त सियुक्त सिप्तक, निक्निसिखित द्वारा लिखित रूप में सुपने की व्यक्तिगत

रूप से दी गई या उसक द्वारा भेजी गई किसी जानकारी या सिकायता को विचार के लिए यहण कर सकेगा, प्रणीत् :--

- (क) भारतीय रिजर्व चैंक ;
- (ख) किसी बैंक या विसीय संस्था;
- (ग) सरकार के किसी प्रवर्तन या अन्वेषण प्रभिकरण या विभाग;
- (घ) सरकार के किसी प्रधिकारी या प्राधिकारी ;
- (ङ) किसी व्यक्ति जो व्यवहारी, प्रभिकर्ताया दलाल के रूप में प्रतिभृतियों के संव्यवहार में लगा हुन्ना है;
- (च) किसी मध्य व्यक्ति जिसके प्रतिभृतियों में मधिकारों या हिताँ पर प्रभाव पड़ता है;

परम्तु अण्ड (ङ) भीर खण्ड (ज) में निर्विष्ट किसी व्यक्ति द्वारा भेजी गई जानकारी या शिकायत ग्रिभिरक्षक द्वारा ग्रहण नहीं की जाएगी यदि उसके साथ उस व्यक्ति द्वारा हस्ताकारित भीर किसी मिलस्ट्रेट या नोटरी पश्लिक द्वारा सम्यक्ष रूप से सत्यापित जानय-पत्न नहीं है।

- (3) वे मामले जिन्नें प्रशिरलक जानकारी की अस्वीकार कर सकेंगा: जहां किसी जानकारी या क्रिकायत के साथ उस जानकारी या क्रिकायत में निर्विष्ट दस्तावेजों की प्रतियो नहीं हैं, या वह स्पष्ट नहीं है या उसमें प्रेवक का नाम मौर पता नहीं है वहां ऐसी जानकारी या क्रिकायत को प्रभिरलक मस्वीकार कर सकेंगा।

[फा.सं. 6/2/92 सत. (i)] के.जे. रेड्डी, प्रतिरिक्त स**ीवव**

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 1992

G.S.R. 585(E):—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Ordinance, 1992, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- 1. Short title and commencement:
- (1) These rules may be called the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Rules, 1992.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Sources of information: The Custodian appointed under sub-section (1) of section 3 of the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Ordinance, 1992 (hereinafter

referred to as the Ordinance) may entertain for consideration any information or complaint in writing submitted personally or sent by post to him by—

- (a) the Reserve Bank of India;
- (b) any bank or financial institution;
- (c) any enforcement or investigating agency or department of the Government;
- (d) any officer or authority of the Government;
- (e) any person who is engaged in transactions of securities as a dealer, agent or bloker:
- (f) any other person whose rights or interests in securities are affected:

Provided that the information or complaint sent by any person referred to in clauses (e) and (f) shall not be entertained by the Custodian if it is not accompanied by an affidavit signed by that person and duly verified by a Magistrate or a Notary Public.

- 3. Cases in which Custodian may reject information: Where an information or a complaint is not accompanied by copies of documents referred to in the information or complaint or is vague or does not contain the name and address of the sender, such information or complaint may be rejected by the Custodian.
- 4. Condition for making notification: If the material information or the documents received by the Custodian are sufficient in his opinion, to constitute an offence referred to in sub-300tion (2) of section 3 of the Ordinance, he may proceed to notify the name of the person under that sub-section.

[No. F.6/2/92 Vig.(i)] K.J REDDY, Additional Secy.